>

Title: Need to take steps to construct high dam in Nepal so that floods in Bihar can be prevented.

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार की विभीषिका के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बिहार के लगभग एक दर्जन से ज्यादा जिले पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, सहरसा, किशनगंज ,कटिहार, अररिया, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी ये सारे जिले बाढ़ से अति प्रभावित हैं । यह बाढ़ मुख्य तौर से नेपाल में जो अत्यधिक बारिश हुई है,उसके कारण आई है । बिहार-नेपाल से होकर जो नदियां निकलती हैं उनका जल स्तर इतना बढ़ गया है कि पूरे उत्तर बिहार में भयावह स्थिति हो गई है । राज्य सरकार अपने स्तर पर जो काम करना है, कर रही है, राज्य सरकार वहां राहत शिविर चला रही है । राज्य सरकार ने एसओपी बनाया है, वहां के मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि राज्य कोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ित लोगों का है, इसलिए राज्य कोष की कोई समस्या नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इसका स्थायी समाधान ढूंढा जा सके । स्थायी समाधान के लिए नेपाल परिक्षेत्र में उनकी नदियों के ऊपर हाई डैम बनाए जाएं और उसके बाद बाढ़ पर भी नियंत्रण हो सकेगा और पनबिजली की योजनाओं पर भी काम हो सकेगा ।

इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि नेपाल सरकार के साथ मध्यस्थता करके, बातचीत करके नेपाल मे हाई डैम बनाने की दिशा में सरकार तत्काल सकारात्मक पहल करे ताकि बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सके और स्थायी समाधान हो सके । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रेखा वर्मा, श्री दिनेश चन्द्र यादव, श्री संतोष कुमार, श्री विजय कुमार, श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी, श्री सुनील कुमार पिंटू, डॉ. आलोक कुमार सुमन, श्री गिरिधारी यादव, श्री दिलेश्वर कामैत,

श्री जगदम्बिका पाल एवं श्री राम कृपाल यादव को श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

माननीय मंत्री जी, क्या आप कोई वक्तव्य देना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य पिंटू जी, आप बैठ जाइए । माननीय मंत्री जी आपके राज्य बिहार से ही आते हैं । आपको माननीय सदस्य श्री राजीव रंजन सिंह जी के साथ एसोसिएट कर दिया है ।

...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): अध्यक्ष महोदय, जैसे ही देश के विभिन्न भागों से बारिश की सूचना प्राप्त होने लगी और बाढ़ की आशंका बढ़ी, ठीक उसी समय पर माननीय गृह मंत्री जी ने 12 जुलाई को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और उसकी समीक्षा की गई । गृह मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को माननीय गृह मंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि सभी राज्यों से सम्पर्क में रहें और जितनी आवश्यकता हो, सहायता पहुंचाने की जो अपेक्षा हो, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए । माननीय गृह मंत्री जी ने अपने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है । इसके परिणाम भी अच्छे आए हैं । बिहार, असम, निश्चित रूप से जिनकी ज्यादा चर्चा हो रही है, और कुछ अन्य राज्यों में भी आंशिक रूप से बाढ़ का प्रभाव है । ...(व्यवधान) पूर्वी उत्तर प्रदेश भी उनमें शामिल है । अन्य राज्यों में भी आंशिक प्रभाव पड़ा है । अपने यहां इस आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार ने बड़ी तत्परता से पहल की है । असम सरकार, बिहार सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ

यह प्रयास किया है कि बाढ़ से पीड़ित लोगों की जान-माल की रक्षा हो, कम से कम क्षति हो और बाढ़ के समय लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं । राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से जो भी अपेक्षा रखी, बड़ी तत्परता के साथ उसे पूरा भी किया गया है । बिहार में पहले से ही एनडीआरएफ की 12 टीम्स काम कर रही हैं । वहां से एनडीआरएफ की पांच टीम्स और भेजने की सूचना प्राप्त हुई थी । सूचना प्राप्त होते ही, बिना किसी दूसरी प्रक्रिया का इंतजार किए हुए, तत्क्षण ही पांच की जगह पर सात एनडीआरएफ की टीम्स को बिहार के लिए रवाना किया गया और यह सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी को दी गई । ...(व्यवधान) मेरी बात सुनिए । मैं भी कह ही रहा हूं कि राज्य सरकार ने राहत शिविर लगाए हैं । ...(व्यवधान) मैंने अभी एनडीआरएफ के बारे में बताना शुरू ही किया है, उसके बाद मैं एसडीआरएफ पर भी आ रहा हूं । ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं उस विषय पर भी आ रहा हूं । थोड़ा धैर्य रखिए।...(व्यवधान)

वहां से लगभग 11 बजे सूचना मिली और शाम को छ: बजे बनारस से सात टीमें पहुंच गईं । इस प्रकार से बिहार में 19 एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं । यदि वहां उनकी और जरूरत होती तो और भेजी जातीं, इसलिए अधिकारियों ने रिजर्व में भी एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात करके रखी थीं । असम में भी 18 एनडीआरएफ की टीमें लगाई गईं । मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि इस वक्त आप एसडीआरएफ की चिंता कर रहे हैं । एसडीआरएफ को पांच राज्यों के लिए 3,569 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया । एनडीआरएफ और एसडीआरएफ डिजास्टर मैनेजमेंट देखता है, उसका एक बड़ा पार्ट है । ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार ने एनडीआरएफ से पांच राज्यों और एसडीआरएफ से 15 राज्यों को 41,022 करोड़ रुपये की धन राशि दी है । बिहार राज्य को 417 करोड़ रुपये और असम राज्य को 251 करोड़ रुपये अतिरिक्त धन राशि का प्रावधान किया गया है । अन्य राज्यों में भी बाढ़ की संभावना बनी रहती है । अभी खास कर बिहार और असम बाढ़ प्रभावित राज्य हैं, उन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है । एनडीआरएफ की 121 टीमें इस मॉनसून के दौरान तैनात की गई हैं । असम की माननीय सदस्या बोल रही थीं कि पहले बाढ़

में भयावह स्थिति होती थी, भारी मात्रा में जान-माल की क्षति होती थी, संपत्ति की क्षति होती थी । अब क्षति हुई है, यह दु:ख का विषय है, लोगों की जानें भी गई हैं, लेकिन कम मात्रा में गई हैं, यह भी नहीं होना चाहिए । लेकिन यह हुई है, लेकिन कम हुई है, यह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की तत्परता की देन है ।

अध्यक्ष महोदय, अब तक मॉनसून में कुल 11,465 प्रभावित लोगों की जान पर खतरा था । अगर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की तत्परता नहीं रहती तो बिहार और असम में दो हजार लोगों की जानें चली जातीं और अपना देश दु:ख के माहौल में होता । दु:ख का माहौल तो है ही, लेकिन क्षति को बहुत कम किया गया है । एक हजार जरूरतमंद लोगों को एनडीआरएफ द्वारा चिक्तिसीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है । माननीय सांसद ललन बाबू चर्चा कर रहे थे, जो बिहार में सिंचाई विभाग के मंत्री रहे हैं । उनकी चिंता स्वाभाविक है और स्थायी समाधान भी यही है कि नेपाल में एक ऊंची बांध बनाई जाए, ताकि दोनों काम हो सके, पानी को नियंत्रित भी किया जा सके और किसानों को सिंचाई के लिए पानी जरूरत पड़ने पर दिया जा सके।... (व्यवधान) उससे पनबिजली, सिंचाई और बाढ़ पर नियंत्रण, तीनों काम होंगे । ... (व्यवधान)

सुबोध जी, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी नेपाल के कुछ माननीय सांसद आए थे और जब उनसे इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि यह काम भारत और नेपाल मिल कर लेते हैं तो जो बिहार, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड से लगे हुए नेपाल के इलाके हैं, उनमें भी किसानों को बहुत फायदा होगा । वहां से सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है । वहां अच्छे रूप से पनबिजली का उत्पादन भी हो सकता है । वहां बिजली का उत्पादन सुगमता से हो सकता है । नेपाल में हाई डैम बनाना एक अंतराष्ट्रीय मामला है । इसके लिए भारत का प्रयास है, माननीय मोदी जी का प्रयास है, केन्द्र की सरकार का प्रयास है और इस पर पहल करने का प्रयास हो रहा है । ...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): These matters can be raised by way of a discussion under Rule 193. …(*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): He is already responding. Then, why do you need a discussion under Rule 193?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, यह अंतर्राष्ट्रीय मामला होने के कारण कई पहलुओं पर जितनी सफलता मिलनी चाहिए, उतनी सफलता नहीं मिल रही है ।...(व्यवधान) माननीय सांसद सुनील जी, आप भरोसा रखिए, मोदी जी की सरकार है । मोदी जी की सरकार पर देश और दुनिया ने भरोसा किया है । माननीय सांसद आप भी भरोसा रखिए और अच्छे दिन आए हैं, आगे भी आएंगे । मोदी है तो मुमकिन है और शाह है तो सिद्धि है । आप चिंता मत कीजिए ।

महोदय, प्रयास जारी है और सफलता भी मिलने की आशा है । माननीय सदस्यों की जो चिंता है या केंद्र की जो चिंता है, माननीय प्रधान मंत्री जी की चिंता है, माननीय गृह मंत्री जी की चिंता है, सबकी चिंता है, उसके लिए बाढ़ का स्थायी समाधान खोजा जा सके, इसके लिए प्रयास भी जारी है और विचार भी हो रहा है ।